आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 20 लखनऊ, शुक्रवार 28 अगस्त 2026 सा 06 सितम्बर 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

नेपाल–चीन सीमा पर कुदरत का कहरः १,३८४ लोग लापता, १६० से ज्यादा मौतें

लखनऊ। नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र में बुधवार को आयी विनाशकारी बाढ़ के बाद १,३०० से अधिक लोग अब भी लापता हैं और १६० से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बाढ़ ने सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि कई इलाके संपर्क से कटे होने के कारण बचाव दलों को प्रभावित लोगों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। नेपाली अधिकारियों के अनुसार, नेपाल की ओर ८२६ लोग लापता हैं, जिनमें कम से कम ३०० विदेशी नागरिक शामिल हैं। वहीं चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के ग्यिरोंग काउंटी में ५५८ लोगों के लापता होने की सूचना है। दोनों देशों के आंकड़ों को मिलाकर लापता लोगों की संख्या कम से कम १,३८४ हो गयी है। अधिकारियों ने हालांकि कहा कि संचार व्यवस्था बहाल होने और बचाव दलों के प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के साथ यह आंकड़ा बदल सकता है। यह आपदा बुधवार को उस समय आयी जब पहाड़ी घाटियों में पानी, मलबे और कीचड़ के तेज प्रवाह ने घरों, वाहनों और व्यावसायिक इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया और कई बस्तियां तबाह हो गयीं। स्थानीय मीडिया ने बताया कि भोटेकोशी की सहायक नदी ल्हेंदे के प्रवाह के हिमस्खलन से अवरुद्ध होने के बाद अचानक पानी का भारी दबाव बना और बाढ़ ने सबसे पहले चीन की सीमा से लगे रसुवा जिले के तिमुरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया। सैकड़ों लोगों की आबादी वाला यह इलाका देखते ही देखते बह गया और इसके बाद बाढ़ का पानी नीचे की ओर बढ़ गया। क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण लोगों को किसी बड़ी बाढ़ की आशंका नहीं थी और वे

रोजमर्रा के काम में लगे थे। बाढ़ के कारण पुलों के ढहने, सड़कों के मलबे में दबने और लगातार भूस्खलन से राहत एवं बचाव कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चीन की ओर आपातकालीन दल करीब २२ घंटे बाद ग्यिरोंग बंदरगाह पहुंचे। खराब मौसम और अवरुद्ध सड़कों के कारण उन्हें पहुंचने में देरी हुई। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, १४१ बचावकर्मियों का पहला दल बंदरगाह पहुंचा और एक ऊंचाई वाले क्षेत्र में काम करने वाला एमआई–१७१ हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया। ग्यिरोंग बंदरगाह की ओर जाने वाली सड़क का करीब १.५ मीटर हिस्सा मलबे में दबा है। बंदरगाह से करीब २.५ किलोमीटर पहले से रास्ता अवरुद्ध है। बाढ़ के पानी ने सीमा परिसर की एक सरकारी इमारत समेत आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल में सड़क और पुलों के तबाह होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों पर निर्भरता बढ़ गयी है। सीएनएन की एक रिपोर्ट में नेपाली सांसद सुमनिमा उदास के हवाले से कहा गया कि सेना ने उपलब्ध सभी हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है और निजी हेलीक प्टर संचालकों की भी मदद ली जा रही है। राहत सामग्री लेकर भेजे जा रहे ट्रक भी कई स्थानों पर सड़कें नष्ट होने के कारण अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ में नौ जलविद्युत परियोजनाएं और नौ वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं तबाह हो गयी हैं। इसके अलावा १६ मोटर योग्य पुल और करीब ४० किलोमीटर राजमार्ग बह गये हैं। निजी और सरकारी संपत्ति को हुए कुल नुकसान का अभी आकलन नहीं हो सका है। बाढ़ में जलविद्युत परियोजनाओं, बैंकों, सीमा शुल्क कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कई लोग भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्र में फंसे विदेशी पर्यटकों की तलाश के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने यह संभावना भी जतायी है कि ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर घाटी में गिरा हो, जिससे भूस्खलन शुरू या और अधिक गंभीर हुआ हो। बाढ़ में भूस्खलन और संभावित ग्लेशियर टूटने की भूमिका का पूरा आकलन अभी बाकी है। भारत ने नेपाल के लिए राहत और मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत की ओर से गुरुवार को ३७.५ टन राहत सामग्री, दवाइयां और खाद्य पैकेट लेकर दूसरी उड़ान नेपाल भेजी गयी। इससे पहले बुधवार को भारत ने १० टन राहत सामग्री भेजी थी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की एक टीम को फिलहाल नेपाल नहीं भेजा गया है, हालांकि टीमें तैयार रखी गयी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर जनहानि पर दुख जताया और कहा कि भारत नेपाल को हरसंभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। नेपाल और चीन में स्थित भारतीय दूतावासों ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन भी स्थापित की हैं। बाढ़ से ग्यिरोंग बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा है, जो २०२४ में चीन–नेपाल के बीच होने वाले व्यापार के करीब एक–तिहाई हिस्से को सुगम बनाता था। इस क्षेत्र में पिछले वर्ष भी बाढ़ से ग्यिरोंग पुल क्षतिग्रस्त हुआ था और उसने २०२६ की शुरुआत में ही काम करना शुरू किया था। इस बीच, पूर्व एनडीआरआरएमए प्रमुख अनिल पोखरेल ने कहा कि नेपाल और चीन के बीच ऐसी आपदाओं के लिए सूचना साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल आपदा के बाद राहत और बचाव तक सीमित रहने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे समय रहते लोगों की जानें बचायी जा सके। बाढ़ के बाद नेपाल के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग और चीन के मौसम प्रशासन के अधिकारियों के बीच बुधवार को ऑनलाइन बैठक हुई। इसके बाद चीन ने सहमति जताई कि अपनी ओर पानी का स्तर बढ़ने पर वह नेपाल को तत्काल सूचना देगा। नेपाल और चीन ने २०१६ में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपात प्रतिक्रिया में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। इसमें सूचना साझा करने, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, प्रशिक्षण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं समेत नौ क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है।

नेपाल बाढ़ः वायु सेना के विमान राहत सामग्री ले जाने के लिए तैयार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेपाल को भीषण बाढ़ की स्थिति से निपटने में भारत की ओर से हर संभव मानवीय सहायता पहुंचाने के आश्वासन के बाद भारतीय वायु सेना के रणनीतिक परिवहन बेड़े के विमान वहां प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर जाने के लिए तैयार हैं। भारत की ओर से यह कदम नेपाल–तिब्बत सीमा के पास बुध ावार को भोटे कोशी नदी में अचानक आयी विनाशकारी बाढ़ के बाद उठाया जा रहा है। बाढ और भूस्खलन के कारण ३० लोगों की मौत हो गयी, कई सौ लोग लापता हैं और बस्तियों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि वायु सेना का एक सी–१३०जे परिवहन विमान आज राहत सामग्री, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामान लेकर नेपाल के लिए उड़ान भर सकता है जबकि एक सी–१७ विमान गुरुवार को उसके बाद रवाना होने वाला है। इस बीच नेपाल में बाढ के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने बिहार में अपनी तैनाती मजबूत कर दी है। राज्य के संवेदनशील हिस्सों में एनडीआरएफ की नौ टीमें तैनात हैं, जिनमें नेपाल में बदलती स्थिति के मद्देनजर भेजी गई अतिरिक्त टीमें भी शामिल हैं। एनडीआरएफ के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने मीडिया से कहा कि बल ने मानसून की तैयारियों के तहत पहले ही बाढ़ संभावित क्षेत्रों में टीमें तैनात कर दी थीं और बाद में नेपाल की

स्थिति से निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने की संभावित आशंका सामने आने के बाद तैनाती को और मजबूत किया गया। चिंता इस संभावना से उत्पन्न हुई है कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों से पानी भारतीय क्षेत्र में, विशेष रूप से दोनों देशों को जोड़ने वाली नदी प्रणालियों के माध्यम से, आ सकता है। इसलिए बिहार में अधि ाकारी जलस्तर पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर निकासी, बचाव तथा राहत अभियानों के लिए तैयार हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों से ३८४ यात्रियों के लापता होने की सूचना है, जिनमें २६१ विदेशी नागरिक और ६३ नेपाली नागरिक हैं। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वह पर्यटक पुलिस और पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद या वहां से यात्रा कर रहे लोगों के ठिकाने और सुरक्षा का पता लगाने के लिए काम कर रहा है। सूची में १०५ भारतीय नागरिक और ३७ अनिवासी भारतीय शामिल हैं। ये आंकड़े प्रारंभिक हैं और अधिकारी सूची में शामिल लोगों के ठिकाने और सुरक्षा का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रध ानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष बालेन्द्र शाह से बात की और जानमाल के नुकसान पर भारत की संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है और आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल की जनता के साथ खड़ा है।

सम्पादकीय

''समृद्ध उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या या बढ़ती आर्थिक विषमता?''

मार्केट रिसर्च एजेंसी नीलसन–आईक्यू की ताजा रिपोर्ट में यह अनुमान सामने आया है कि अगले दस वर्षों में भारत 'समृद्ध उपभोक्ताओं' की संख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष २०३६ तक भारत में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या करीब १०.८ करोड़ हो सकती है, जबकि चीन में यह आंकड़ा लगभग १०.३ करोड़ रहने का अनुमान है। पहली नजर में यह आंकड़ा भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत होते बाजार और बढ़ती क्रय शक्ति की उत्साहजनक तस्वीर पेश करता है। स्वाभाविक रूप से इस अनुमान को लेकर बाजार और उद्योग जगत के कुछ हिस्सों में सुखबोध दिखाई देना भी असामान्य नहीं है। लेकिन किसी भी आर्थिक आंकड़े की वास्तविक तस्वीर उसके पीछे छिपे अर्थ को समझे बिना पूरी नहीं होती। सवाल यह नहीं है कि भारत में कितने लोग महंगी वस्तुएं खरीदने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, बल्कि यह है कि ''क्या देश के व्यापक समाज की आय और जीवन स्तर भी उसी गति से ऊपर जा रहा है?'' नीलसन–आईक्यू ने 'समृद्ध उपभोक्ता' की जो परिभाषा तय की है, उसके अनुसार ऐसे लोग औसतन प्रतिदिन ६० ड लर यानी लगभग ८,५०० रुपये से अधिक खर्च करने की क्षमता रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह आकलन किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति, नियमित आय या सामाजिक सुरक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि उसके उपभोग और क्रय शक्ति के आधार पर किया गया है। इसलिए इस आंकड़े को सीधे–सीधे भारत में समृद्धि बढ़ने का प्रमाण मानना सावध ानी से परे होगा। फिलहाल भारत में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या लगभग २.६ करोड़ बताई गई है। यदि वर्ष २०३६ तक यह संख्या १०.८ करोड़ पहुंचती है तो एक दशक में इसमें तीन गुने से भी अधिक की वृद्धि होगी। यह निश्चित रूप से भारतीय बाजार के आकार और उपभोग की क्षमता में बड़े बदलाव का संकेत होगा। लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए यह भी देखना होगा कि इस बढ़ती खपत का लाभ समाज के कितने हिस्से तक पहुंच रहा है और कितने लोग अब भी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले कुछ वर्षों में 'के–शेप' वृद्धि की चर्चा लगातार होती रही है। इसका आशय ऐसी आर्थिक वृद्धि से है जिसमें समाज के एक हिस्से की आय और संपत्ति तेजी से बढ़ती है, जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा उसी गति से आगे नहीं बढ़ पाता या उसकी वास्तविक क्रय शक्ति कमजोर बनी रहती है। कोरोना महामारी के बाद यह अंतर और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। एक ओर उच्च आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए महंगी कारों, प्रीमियम इलेक्ट्र निक्स, विदेशी पर्यटन, लग्जरी ब्रांड, महंगे आवास और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में मांग बनी रही, वहीं दूसरी ओर बड़ी आबादी के लिए खाद्य पदार्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताएं ही आर्थिक चिंता का केंद्र बनी हुई हैं। इसलिए यदि आने वाले दस वर्षों में भारत में समृद्ध उपभोक्ताओं की संख्या चार गुनी होने के करीब पहुंचती है, तो यह अपने आप में बुरी खबर नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब समृद्धि का यह विस्तार समाज के सीमित हिस्से तक ही केंद्रित रह जाए और उसके समानांतर आर्थिक विषमता भी बढ़ती जाए। नीलसन की रिपोर्ट बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े कारोबारी समूहों के लिए निश्चित रूप से आकर्षक है। १० करोड़ से अधिक उच्च–खर्च क्षमता वाले उपभोक्ताओं का बाजार दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। लक्जरी कारों से लेकर स्मार्टफोन, इलेक्ट्र निक्स, पर्यटन, प्रीमियम स्वास्थ्य सेवाओं, निजी शिक्षा, फैशन, मनोरंजन और उच्चस्तरीय आवास तक अनेक क्षेत्रों में मांग बढ़ सकती है। भारत वैश्विक कंपनियों के लिए चीन के विकल्प के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण बाजार बन सकता है। लेकिन बाजार की सफलता को सामाजिक प्रगति का पर्याय मान लेना उचित नहीं होगा। किसी देश में महंगे उत्पादों की बिक्री बढ़ना और आम नागरिक की आर्थिक सुरक्षा बढ़ना दो अलग–अलग बातें हैं। यदि देश की बड़ी आबादी अपनी आय का अधिकांश हिस्सा भोजन, किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी आवश्यकताओं पर खर्च करने के लिए मजबूर है, तो कुछ करोड़ लोगों की बढ़ती विलासिता को समूचे देश की समृद्धि का प्रमाण नहीं माना जा सकता। पिछले वर्षों में सामने आए विभिन्न अध्ययनों ने भी भारत में आय और उपभोग की असमानता की ओर संकेत किया है। यदि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य खरीदारी करने की स्थिति में नहीं है, तो हमें यह पूछना होगा कि आर्थिक वृद्धि का लाभ किस अनुपात में वितरित हो रहा है। आर्थिक विकास का असली मूल्यांकन केवल सकल घरेलू उत्पाद, शेयर बाजार या लग्जरी वस्तुओं की बिक्री से नहीं होना चाहिए। यह भी देखना होगा कि रोजगार कितने पैदा हुए, वास्तविक मजदूरी कितनी बढ़ी, छोटे कारोबार कितने मजबूत हुए, ग्रामीण परिवारों की आय में कितना सुधार हुआ और स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर परिवारों का आर्थिक बोझ कितना घटा। यदि इन सवालों के जवाब कमजोर हैं, तो बढ़ती उपभोक्ता संख्या की चमक के पीछे एक गहरी असमानता छिपी हो सकती है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा– ६७ करोड़ मतदाताओं के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा परिवार

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि भारत के लगभग ६७ करोड़ मतदाता मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा परिवार बनाते हैं और जब लोकसभा चुनाव होते हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग धरती का सबसे बड़ा संगठन बन जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, कुमार ने ये बातें लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चुनाव साक्षरता क्लब (ईएलसी) २.० और ईसीआईनेट के क्षेत्रीय सम्मेलन में कहीं। ज्ञानेश कुमार ने कहा, भारत में लगभग ६७ करोड़ मतदाता हैं। इसका क्या मतलब है? यह सिर्फ एक संख्या नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अलग–अलग देशों में मतदाताओं की आबादी के हिसाब से ६७ करोड़ कितना होता है? अगर आप अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, पूरे यूरोप, पूरे अफ्रीका और पूरे दक्षिण–पूर्व एशिया के मतदाताओं को भी जोड़ लें, तब भी यह भारत के मुकाबले आठ करोड़ कम रह जाती है। आप इतने बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। कुमार ने

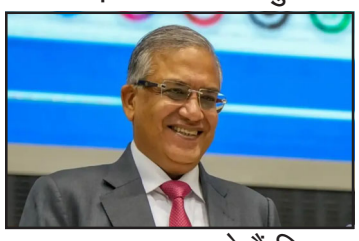

कहा, क्या आप जानते हैं कि जब भारत का निर्वाचन आयोग (ईसीआई) लोकसभा चुनाव कराता है तो यह काम कितने बड़े पैमाने पर होता है? जब लोकसभा चुनाव होते हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग धरती का सबसे बड़ा संगठन बन जाता है, जिसके साथ १.८ करोड़ लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। कुमार ने उपस्थित लोगों से सवाल किया कि इन १.८ करोड़ लोगों के साथ बातचीत या संपर्क कैसे होता है? उन्होंने कहा, वे सभी ईसीआईनेट के जरिये जुड़े हुए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से लेकर पीठासीन अधिकारी और मतगणना अधिकारी तक, हर कोई इस माध्यम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में ट्विटर (जिसे अब एक्स कहा जाता है) को ढाई करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, लेकिन चार–पांच महीने पहले शुरू किया गया ईसीआईनेट इस साल के आखिर तक यह भारत का सबसे बड़ा ऐप बन जाना चाहिए, क्योंकि इसमें १६५५२ के लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक की सारी जानकारी मौजूद है... चाहे वह किसी बूथ पर वोटिंग की संख्या हो, किसी उम्मीदवार को मिले वोट हों या हलफनामे हों।

KGMU की डॉ. नीतू सिंह की बर्खास्तगी भ्पही Court ने रद्द की, बहाली का दिया आदेश

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नीतू सिंह को सेवा से हटाने का फैसला रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि डॉ. सिंह के खिलाफ की गई विभागीय जांच निर्धारित नियमों और प्रोंतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की अदालत ने मंगलवार को दिए आदेश में केजीएमयू को निर्देश दिया कि डॉ. सिंह को सेवा में बहाल किया जाए और उन्हें सेवा से जुड़े सभी लाभ दिए जाएं, जिसमें बकाया वेतन का भुगतान भी शामिल है। यह मामला वर्ष २०२० में डॉ. सिंह के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़ा है। उस समय वह केजीएमयू की म लिक्यूलर बायोल जी प्रयोगशाला में एसोसिएट प्रोफेसर (नॉन–मेडिकल) के पद पर कार्यरत थीं। डॉ. सिंह पर चार आरोप लगाए गए थे, जिनमें एक स्वास्थ्य परियोजना का प्रस्ताव, कथित तौर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन और साहित्यिक चोरी

जैसे आरोप शामिल थे। जांच के बाद १० जून २०२० को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, जिसके बाद उन्हों ने उच्च न्यायालय में सेवा समाप्ति के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि विभागीय जांच के दौरान आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अदालत ने पाया कि जांच समिति ने डॉ. सिंह के खिलाफ इस्तेमाल किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को उचित तरीके से प्रमाणित या परखा नहीं व उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल दिए। पीठ ने माना कि सेवा समाप्ति का आदेश और उससे संबंधित कार्रवाई मनमानी तथा कानून के विरुद्ध थी। पीठ ने हालांकि केजीएमयू को ड . सिंह का जवाब प्राप्त होने के चरण से नई विभागीय जांच शुरू करने की छूट दी है। अदालत ने निर्देश दिया कि नई जांच लागू 'अनुशासन और अपील नियमों' के नियम संख्या सात के अनुसार की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि पुनर्गठित जांच समिति में किसी कानूनी विशेषज्ञ को शामिल किया जाता है तो ड . सिंह को भी कार्यवाही के दौरान कानूनी सहायता लेने का अधिकार होगा।

कृषक समाज इंटर कॉलेज में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया

गोला गोकर्णनाथ खीरीं कृषक समाज इंटर कॉलेज में रक्षाबंधन का त्योहार प्रधानाचार्य अनंत प्रकाश सरोज की अध्यक्षता में हर्षोल्लास एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को राखी बाँधकर भाई–बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कॉलेज के प्रबंधन रवि प्रकाश वर्मा, डॉ पूर्वी वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने छात्राओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह पर्व प्रेम, विश्वास, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द की भावना को मजबूत करता है। विद्यालय के शिक्षकों ने भी छात्राओं को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएँ दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला।विद्यालय परिवार ने रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को आपसी प्रेम, सम्मान और भाईचारे के साथ मनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य लखपत भारती डॉ अनिल कुमार ओम प्रकाश यादव सहित सभी समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे संचालन देवेंद्र सिंह ने कियां

रक्षाबंधन से पहले मिठाइयों का काला सच उजागर, लखनऊ में ४.६२ लाख का माल सीज

लखनऊ। वर्ष २०२६ में रक्षाबंधन २८ अगस्त यानी कल शुक्रवार को मनाया जाएगा, लेकिन इसकी तैयारियों बीते कई दिनों से चल रही हैं। रक्षाबंधन पर लोग मिठाइयों की खूब खरीदारी करते हैं, लेकिन त्योहार के बीच ही

लखनऊ, सीतापुर,गोण्डा, श्रावस्ती, जालौन समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई में मिठाइयों का जो सच सामने आया है, उसने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लखनऊ के एफएसडीए टीम ने शनिवार से गुरुवार के बीच कई मिठाइयों के निर्माण इकाइयों और दुकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की है, लखनऊ के जिन इलाकों में कार्रवाई हुई है उनमें बंथरा–बिजनौर रोड, काकोरी, मलिहाबाद, कठौली और नादरगंज में स्थित निर्माण इकाइयां शामिल हैं। छापेमारी के दौरान टीम ने पेड़ा, रिफाइंड सोयाबीन तेल, चांदी के वर्क वाली बरफी, बेसन लड्डू, काला जाम, पेड़ा, कलाकंद सहित कई खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल ने गुरुवार को नीवा

कासिम खेड़ा स्थित रिंकू की मिठाई निर्माण इकाई का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए टीम ने पेड़ा, रिफाइंड सोयाबीन तेल चांदी के वर्क का नमूना लिया। जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। संदिग्ध गुणवत्ता पाए जाने पर मौके से १८० लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल को सीज कर दिया। बाजार में इसकी अनुमानित किमत ४०,८६० के करीब बताई जा रही है,इसके अलावा परिसर में मिली २०० किलो मिठाइयों को भी नष्ट कर दिया गया है। जांच अधिकारियों ने बताया कि जिन मिठाइयों का निर्माण यहां हुआ था वह मानव के उपयोग करने लायक नहीं थीं। वहीं संचालक की तरफ से वैध खाद्य लाइसेंस भी नहीं दिखाया गया, जिसके कारण इस निर्माण इकाई को ही बंद करा दिया गया है। शनिवार को काकोरी के हरदोईया लाल नगर में स्थित शिवाछी स्वीट्स हाउस खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जांच करने पहुंची थी, जिस जगह पर मिठाइयों को बनाने का काम हो रहा था, वहां चारो तरफ गंदगी ही गंदगी थी। मिठाई निर्माण की जगह पर गंदा पानी और मक्खियों का जमावड़ा तो था ही, वहां भैंसें भी बंधी थीं। जांच करने पहुंचे अधिकारियों की मानें तो गोबर के छीटे मिठाइयों पर पड़ रहे थे, जो मिठाइयों को दूषित बना रहे थे, गंदे पलास्टिक के ड्रमों में करीब १००० लीटर दूषित घोल था, जिसमें मक्खियां भी पड़ी हुई थीं। जांच के दौरान २६०० किलो से अधिक माल को नष्ट करने के चिन्हित किया गया, साथ ही जिस जगह पर मिठाइयां बन रही थीं, उस कमरे को सील कर दिया गया था। यह मामला तो बानगी मात्र है। एफएसडीए टीम ने बुधवार को मलिहाबाद, कठौली तथा नादरगंज में कार्रवाई करते हुये बेसन लड्डू, बरफी, काला जाम, पेड़ा, कलाकंद सहित २६ खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे। इसके अलावा लगभग ४.६२ लाख मूल्य का कच्चा माल एवं खाद्य सामग्री सीज कराने के साथ ५०,००० मूल्य का खराब मिल्क केक व बरफी मौके पर नष्ट कराई। टीम ने हरदोई रोड स्थित बनिया खेड़ा में आकृति गृह उद्योग का निरीक्षण किया। जिसमें सूजी पेड़ा, लाल पेड़ा, सूजी हलवा, सूजी बरफी एवं कलाकंद का निर्माण होते पाया गया। मौके पर ५०० लीटर चीनी घोल तथा एक क्विंटल दूषित मिठाई नष्ट कराई। इसके अलावा स्थल से लाल पेड़ा, सूजी पेड़ा, कलाकंद, सूजी बर्फी, सूजी हलवा, एसएमपी, रिफाइंड पामोलीन ऑयल एवं चीनी सहित कुल ६ नमूने लिए। टीम को मलिहाबाद तहसील के ग्राम रहीमाबाद में चौराहे पर स्थित रमेश तिवारी की मिठाई दुकान के निरीक्षण में १० क्विंटल विभिन्न मिठाइयां मिलीं। मिलावट के संदेह पर मौके से काला जाम, बेसन लड्डू, बरफी, वर्कयुक्त बरफी, रसगुल्ला, गोंद का लड्डू एवं अनरसा के ७ नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे। ५० किलो मिल्क केक व बरफी खराब पाये जाने पर खाद्य कारोबारी ने मौके पर स्वयं नष्ट करा दिया। नादरगंज स्थित श्याम उद्योग के निरीक्षण मेंएफएसडीए टीम ने मौके से मिल्क केक (गोपिका ब्रांड), कलाकंद, डोडा बर्फी, देसी घी, रिफाइंड सोयाबीन तेल, एसएमपी, सिट्रिक एसिड, वनस्पति एवं काजू बर्फी सहित कुल १० नमूने लिए। खराब ५० किग्रा मिल्क केक एवं मूंगफली दाना मौके पर नष्ट कराया। संदेह के आधार पर परिसर में पाए गए लगभग ४.६२ लाख मूल्य की खाद्य सामग्री सीज कर दी।

पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा, मायावती ने गठबंधन से किया किनारा

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी। चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं मायावती ने यहां पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में पंजाब में जनाधार बढ़ाने और संगठन के कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में यह बात कही। बसपा की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मायावती ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह बिना किसी से गठबंधन किए अकेले लड़ा जाएगा, ताकि चुनावी गठबंधन से सीट और वोट प्रतिशत में होने वाले नुकसान से पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ने वाले असर से बचा जा सके। बसपा प्रमुख ने अगले वर्ष की शुरुआत में प्रस्तावित पंजाब विधानसभा चुनाव में कर्मठ और ईमानदार लोगों को उम्मीदवार बनाने पर जोर दिया, ताकि आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जनविरोधी रवैये से त्रस्त जनता को 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की आंबेडकरवादी नीतियों का लाभ मिल सके। मायावती ने कहा कि यह महान संत गुरु रविदास, बाबा साहेब ड . भीमराव आंबेडकर और बसपा संस्थापक कांशीराम के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने

पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने के लिए दिए गए दिशा–निर्देशों पर मिली प्रतिक्रिया के आधार पर कमियों को समयबद्ध तरीके दूर करने पर जोर दिया। मायावती ने कहा कि बसपा की पंजाब इकाई को नौ अक्टूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम के पुण्यतिथि कार्यक्रम को पूरी तैयारी के साथ सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि १५ जनवरी २०२७ को 'जनकल्याणकारी दिवस' के मौके पर आर्थिक सहयोग को पिछली बार से बेहतर करना है, क्योंकि यह अंबेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है।

अखिलेश का भाजपा सरकार पर आरोप- जनता की संपत्तियां निजी हाथों में सौंपकर किसे पहुंचाया जा रहा लाभ?

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) को ३० वर्ष के लिए लीज पर दिए जाने के फैसले को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने गठन के समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जय प्रकाश नारायण की तस्वीर लगाई थी, लेकिन अब उसी 'जेपी' को बेच दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो एक रुपये अधिक ले ले, लेकिन जेपीएनआईसी उन्हें दे दे। सपा के प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन से पहले अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोहिया सभागार में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। अखिलेश ने महिलाओं को शगुन का लिफाफा देकर बधाई दी। जेपीएनआईसी को लेकर उन्होंने कहा कि इसका निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया था। यदि भाजपा सरकार को लगता था कि इसमें कोई कमी या भ्रष्टाचार है तो उसे पिछले दस वर्षों में जांच करानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जिस ठेकेदार ने काम किया, उसे पूरा भुगतान करने के साथ यह भी लिखवा लिया गया कि वह भविष्य में कोई मुकदमा नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जनता के पैसे से बनाई गई संपत्तियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। उन्होंने

किसान बाजार का जिक्र करते हुए कहा कि उसे भी अपने लोगों को बेच दिया गया। उन्होंने प्लासियो म ल को ४२८.१७ करोड़ रुपये में बेचने और जेपीएनआईसी को ८३१ करोड़ रुपये में दिए जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र पार्क में भी निजी हाथों को गतिविधियों के लिए जगह दी गई है। सवाल यह है कि जनता के पैसे का लाभ आखिर किसे दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, "दिल्ली का बड़ा इंजन बड़ा बेच रहा है और छोटा वाला छोटा बेच रहा है।" सपा अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता में आने पर उन अधिकारियों की जांच कराई जाएगी, जिन्होंने कथित तौर पर बड़े घोटाले किए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें एक अधिकारी ऐसे भी हैं जो गोरखपुर में मुख्य विकास अधिकारी रह चुके हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि गरीबों का पैसा अमीरों की तिजोरी में जा रहा है और प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने एक वास्तुकार का जिक्र करते हुए कहा कि जिस वास्तुकार को जांच के दायरे में लाने और काली सूची में डालने की तैयारी थी, उसे बाद में नयी दिल्ली में रेलवे स्टेशन बनाने का काम दे दिया गया। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

''हिमालय में प्रकृति का प्रचंड प्रहारः बाढ़ नहीं, भविष्य की चेतावनी''

राकेश पाण्डेय ''निश्छल''

नेपाल–चीन सीमा से लगे हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने, चट्टानों और भारी मलबे के अचानक खिसकने से आई विनाशकारी बाढ़ ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान हिमालय की संवेदनशीलता की ओर खींच दिया है। त्रिशूली और भोटेकोशी नदी तंत्र में अचानक आए भीषण सैलाब ने देखते ही देखते गांवों, सड़कों, पुलों, सीमा चौकियों और अन्य बुनियादी ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी संख्या में लोगों की मौत और हजारों लोगों के लापता होने की खबर ने इस त्रासदी की भयावहता को सामने ला दिया है। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में लगातार बढ़ते पर्यावरणीय दबाव और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों का गंभीर संकेत भी है। ग्लेशियरों के टूटने, भूस्खलन, अचानक बनने वाली झीलों और उनके ओवरफ्लो होने की घटनाएं आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकती हैं। ऐसे में नेपाल और चीन के साथ–साथ भारत के लिए भी यह घटना एक बड़ी चेतावनी है। हिमालय दुनिया की सबसे युवा और संवेदनशील पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहां चट्टानों, बर्फ और हिमनदों की संरचना लगातार प्रोंतिक बदलावों से गुजरती रहती है। जब ग्लेशियर का कोई हिस्सा अचानक टूटता है या चट्टानों और बर्फ का विशाल मलबा घाटियों में गिरता है तो उसके साथ भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर तेजी से बढ़ता है। ऐसी स्थिति में सामान्य नदी कुछ ही मिनटों में विनाशकारी सैलाब का रूप ले सकती है। नेपाल–चीन सीमा पर हुई ताजा घटना में भी यही स्थिति दिखाई दी। त्रिशूली और भोटेकोशी नदी तंत्र में पानी, पत्थर, मिट्टी और मलबे का ऐसा प्रवाह आया कि कई इलाकों को संभलने तक का अवसर नहीं मिला। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ऐसे फ्लैश फ्लड के दौरान पारंपरिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली कई बार पर्याप्त साबित नहीं होती। नदी के जलस्तर में वृद्धि के लिए जहां लोगों को घंटों या दिनों का समय मिल सकता है, वहीं ग्लेशियर या भूस्खलन से उत्पन्न अचानक बाढ़ में चेतावनी और तबाही के बीच का समय बेहद कम हो सकता है। आपदा के बाद सबसे बड़ा खतरा केवल बाढ़ का नहीं है। भारी मलबे के कारण नदी के प्रवाह में अवरोध पैदा होने से कई स्थानों पर कृत्रिम अथवा अस्थायी झीलें बन गई हैं। इन झीलों में पानी लगातार जमा होता रहता है और यदि प्राकृतिक या मलबे से बना बांध अचानक टूटता है तो नीचे की ओर फिर एक और विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। इसी आशंका के चलते नेपाल और चीन के सुरक्षा एवं बचाव बलों को कई बार अभियान रोकना पड़ा। प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे बचावकर्मियों के लिए भी यह स्थिति बेहद जोखिमपूर्ण है। एक ओर मलबे में फंसे लोगों को बचाना जरूरी है, तो दूसरी ओर अचानक झील टूटने अथवा पानी का स्तर बढ़ने की आशंका उनके जीवन को भी खतरे में डाल रही है। इसलिए अब राहत एवं बचाव अभियान को केवल तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक संभावित बैरियर झील की निगरानी, उसके जलस्तर का आकलन और संभावित टूटने की स्थिति में नीचे बसे क्षेत्रों को तत्काल चेतावनी देना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। रसुवागढ़ी सीमा चौकी और आसपास का क्षेत्र भारी मलबे, कीचड़ और पत्थरों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों और पुलों के क्षतिग्रस्त होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। त्रिशूली से लेकर चीन सीमा तक अनेक इलाकों में सामान्य आवागमन बाधित हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में राहत सामग्री पहुंचाना भी अपने आप में चुनौती बन जाता है। सड़कें टूटने के कारण ट्रक और अन्य राहत वाहन प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पाते। परिणामस्वरूप हेलीकॉप्टरों पर निर्भरता बढ़ जाती है। लेकिन खराब मौसम, ऊंचाई और लगातार भूस्खलन के बीच हवाई राहत अभियान भी आसान नहीं होता। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि हिमालयी सीमा क्षेत्रों में विकास के साथ–साथ आपदा–रोधी बुनियादी ढांचे पर भी समान ध्यान देना होगा। केवल सड़क और पुल बना देना पर्याप्त नहीं है। इनके निर्माण में भूस्खलन, ग्लेशियर झीलों, नदी के बदलते प्रवाह और भविष्य में बढ़ने वाले जलवायु जोखिमों को शामिल करना होगा। हिमालयी क्षेत्र में बदलती जलवायु परिस्थितियों को लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से चिंता व्यक्त करते रहे हैं। तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों का पीछे हटना, बर्फ के स्वरूप में बदलाव और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का बढ़ना पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को प्रभावित कर रहा है। हालांकि किसी एक आपदा को सीधे जलवायु परिवर्तन का परिणाम घोषित करना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसी घटनाओं की बढ़ती गंभीरता को व्यापक पर्यावरणीय बदलावों के संदर्भ में अवश्य देखा जाना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिमालय को केवल पर्यटन और आर्थिक विकास के स्रोत के रूप में न देखा जाए। यह क्षेत्र करोड़ों लोगों के जीवन, नदियों और पूरे दक्षिण एशियाई पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालय राजनीतिक सीमाओं में बंटा हुआ जरूर है, लेकिन उसकी नदियां, ग्लेशियर और पारिस्थितिकी किसी सीमा को नहीं मानते। नेपाल में होने वाली कोई बड़ी घटना चीन के तिब्बत क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है और हिमालयी नदी तंत्र के माध्यम से उसका प्रभाव भारत तक भी पहुंच सकता है। इसलिए आपदा प्रबंधन में तीनों देशों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। नदियों के

जलस्तर, ग्लेशियर झीलों, भूस्खलन और मौसम संबंधी सूचनाओं को वास्तविक समय में साझा करने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। सीमा क्षेत्रों में स्थापित निगरानी केंद्रों को आधुनिक रडार, उपग्रह, ड्रोन और सेंसर आधारित चेतावनी प्रणालियों से जोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी संभावित ग्लेशियर झील या मलबे के अवरोध का पता पहले ही चल जाए तो हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का समय मिल सकता है। नेपाल के संकट में भारत की मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजना दोनों देशों के पारंपरिक सहयोग और मानवीय संबंधों का उदाहरण है। लेकिन ऐसी आपदाओं के समय सहायता भेजने के साथ–साथ दीर्घकालिक आपदा तैयारी में सहयोग भी आवश्यक है। भारत के पास आपदा प्रबंधन, पर्वतीय बचाव, हवाई राहत और उपग्रह आधारित निगरानी का व्यापक अनुभव है। इस विशेषज्ञता को नेपाल और अन्य हिमालयी देशों के साथ साझा किया जाना चाहिए। नेपाल के साथ सीमा पार आपदा प्रबंधन का एक संयुक्त तंत्र विकसित किया जा सकता है, जिसमें आपातकालीन संपर्क, मौसम चेतावनी, नदी जलस्तर की सूचना, हेलीकॉप्टर सहायता और खोज एवं बचाव दलों के बीच तत्काल समन्वय शामिल हो। हिमालयी क्षेत्र में सड़क, जलविद्युत परियोजनाओं, पर्यटन और व्यापारिक ढांचे का विकास आवश्यक है, लेकिन विकास की गति प्रकृति की क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी परियोजना के निर्माण से प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित होता है, ढलानों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है या संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण होता है तो वह विकास भविष्य में आपदा का कारण बन सकता है। इसलिए हिमालय में हर बड़ी परियोजना के लिए आपदा जोखिम का स्वतंत्र और वैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य किया जाना चाहिए। निर्माण के दौरान पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी को विकास का हिस्सा नहीं माना जा सकता। हर बड़ी आपदा के बाद राहत और बचाव अभियान शुरू होते हैं, सरकारें मुआवजे की घोषणा करती हैं और क्षतिग्रस्त सड़कों–पुलों के पुनर्निर्माण की योजनाएं बनती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि अगली आपदा से पहले हम क्या तैयारी कर रहे हैं? हिमालयी क्षेत्र में जोखिम वाले गांवों का वैज्ञानिक मानचित्रण होना चाहिए। संवेदनशील आबादी के लिए सुरक्षित स्थान पहले से चिन्हित किए जाने चाहिए। स्थानीय लोगों को नियमित रूप से आपदा अभ्यास कराया जाना चाहिए। स्कूलों, अस्पतालों और प्रशासनिक संस्थानों के लिए अलग आपदा प्रतिक्रिया योजनाएं तैयार होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय समुदाय को आपदा प्रबंधन की पहली कड़ी बनाया जाए। पहाड़ों में रहने वाले लोग मौसम और प्रकृति में होने वाले छोटे बदलावों को सबसे पहले महसूस करते हैं। उनकी स्थानीय जानकारी को आधुनिक वैज्ञानिक चेतावनी प्रणाली के साथ जोड़ना बेहद प्रभावी हो सकता है। नेपाल–चीन सीमा की यह त्रासदी पूरी हिमालयी पट्टी के लिए चेतावनी है। आज नेपाल और तिब्बत इसकी चपेट में हैं, कल यही खतरा हिमालय के दूसरे हिस्सों में भी सामने आ सकता है। हिमालय को बचाने का अर्थ केवल ग्लेशियरों को बचाना नहीं है। इसका अर्थ है नदियों, जंगलों, पहाड़ों, गांवों और उन करोड़ों लोगों के भविष्य को सुरक्षित रखना, जिनका जीवन इन पर्वतों से जुड़ा हुआ है। प्रेंति के संकेतों को नजरअंदाज करके किया गया विकास अंततः मानव जीवन के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हिमालयी क्षेत्र के लिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर नए सिरे से विचार किया जाए। ''यह बाढ़ एक त्रासदी जरूर है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक चेतावनी हैंहिमालय के साथ संघर्ष नहीं, सह–अस्तित्व ही भविष्य का रास्ता है।''

ट्रम्प का दावा, अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज से हटाये सभी बारूदी सुरंगे

अमेरिका ने घोषणा की है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य के मुख्य नौवहन मार्ग से सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को साफ कर दिया है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी ओर कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद खदानों को हटा दिया गया है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। श्री ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि नयी खदानें बिछाने वाले किसी भी पोत या नाव को तुरंत और पूरी तरह से नष्ट कर दिया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी स्पेस फोर्स इस पूरे क्षेत्र पर कड़ी नजर रख रही है और खदानें बिछाने के मामले में 'शून्य सहिष्णुता' की नीति लागू है।अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान–ओमान के बीच के इस मध्य

नौवहन मार्ग में युद्ध के दौरान दर्जनों खदानें बिछायी गयी थीं, जो वाणिज्यिक जहाजों के लिए बड़ा खतरा थीं। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी नौसेना के अंडरवाटर ड्रोन और निजी कंपनियों ने १०० से अधि क संदिग्ध खदानों की पहचान कर उन्हें हटाया है। अब इस मुख्य मार्ग के साफ होने से दोनों दिशाओं में जहाजों की आवाजाही आसान होगी, जिससे वैश्विक बाजारों तक कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ सकेगी। दूसरी ओर, इस मुद्दे पर तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और ओमान के विदेश मंत्री बदर अल–बुसैदी के बीच बैठक हुई। दोनों देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य से खदानें हटाने, सुरक्षित नौवहन के लिए अस्थायी संयुक्त गलियारा बनाने और ट्रैफिक प्रबंधन पर तकनीकी चर्चा की है, हालांकि अभी किसी अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होना बाकी है।

रक्षाबंधनः रिश्तों की डोर से सामाजिक दायित्व तक

राकेश पाण्डेय ''निश्छल''

रक्षाबंधन केवल कलाई पर बांधे जाने वाले एक धागे का पर्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय जीवन–दर्शन में रचे–बसे प्रेम, विश्वास, स्नेह, त्याग, कर्तव्य और संकल्प का उत्सव है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पावन पर्व भाई–बहन के आत्मीय रिश्ते को और अधिक मजबूत करता है। राखी का छोटा–सा धागा भावनाओं की वह बड़ी डोर है, जो परिवार को जोड़ती है, रिश्तों में मिठास घोलती है और जीवन में एक–दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराती है। भारतीय संस्कृति में पर्व केवल उत्सव मनाने के अवसर नहीं रहे हैं, बल्कि इनके पीछे गहरे सामाजिक और मानवीय संदेश भी निहित हैं। रक्षाबंधन भी ऐसा ही पर्व है, जो हमें याद दिलाता है कि रिश्ते केवल अधिकारों से नहीं, बल्कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से मजबूत होते हैं। बहन जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो उसके भीतर प्रेम, विश्वास और मंगलकामना की भावना होती है और भाई भी उसके सम्मान, सुरक्षा तथा हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है।

''रक्षा सूत्र में छिपा विश्वास''

राखी का धागा देखने में भले ही बहुत साधारण हो, लेकिन इसके साथ जुड़ी भावनाएं असाधारण होती हैं। यह धागा भाई–बहन के बीच विश्वास का प्रतीक है। बहन के लिए भाई केवल एक रिश्तेदार नहीं, बल्कि जीवन की अनेक परिस्थितियों में भरोसे का साथी होता है। वहीं भाई के लिए बहन परिवार की उस आत्मीय कड़ी का प्रतीक है, जिसकी खुशियां उसके जीवन को भी आनंद से भर देती हैं। समय बदलता रहा, परिवारों का स्वरूप बदलता रहा और जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहीं, लेकिन रक्षाबंधन की भावना आज भी उतनी ही जीवंत है। दूर–दराज रहने वाले भाई–बहन भी राखी के अवसर पर एक–दूसरे को याद करते हैं। डाक, संदेश, फोन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी यह रिश्ता अपनी आत्मीयता बनाए रखता है। इससे स्पष्ट है कि रिश्तों की दूरी भले बढ़ जाए, भावनाओं की दूरी नहीं बढ़नी चाहिए।

''बहन–बेटियों के सम्मान का संकल्प''

रक्षाबंधन का संदेश केवल भाई–बहन तक सीमित नहीं है। यह समाज को बहन–बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के प्रति जागरूक करने वाला पर्व भी है। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहां महिलाओं और बेटियों को कितना सम्मान, अवसर और सुरक्षा प्राप्त है। आज रक्षाबंधन के अवसर पर केवल अपनी बहन की रक्षा का संकल्प पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज की प्रत्येक बेटी के सम्मान और सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। बेटी चाहे अपने घर की हो या किसी दूसरे परिवार की, उसके सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का सामाजिक दायित्व है। यदि रक्षाबंधन की भावना हमारे व्यवहार में उतर जाए तो महिलाओं के प्रति सम्मान केवल एक दिन का संकल्प न रहकर हमारे जीवन का संस्कार बन सकता है। यही इस पर्व की वास्तविक सार्थकता होगी।

''पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का भाव''

भारतीय परंपरा में रक्षाबंधन से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। भगवान श्रीकृष्ण और द्रौपदी की कथा में स्नेह और आत्मीयता का भाव दिखाई देता है। इसी प्रकार माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी कथा भी रक्षा सूत्र की भावना को अभिव्यक्त करती है। इन कथाओं का महत्व केवल धार्मिक संदर्भों तक सीमित नहीं है। इनके माध्यम से भारतीय समाज ने प्रेम, विश्वास, वचन, कर्तव्य और संरक्षण जैसे मूल्यों को पीढ़ी–दर–पीढ़ी आगे बढ़ाया है। रक्षा सूत्र हमें यह संदेश देता है कि संबंधों की वास्तविक शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि एक–दूसरे के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी में होती है।

''रिश्तों में बढ़ती दूरी के दौर में रक्षाबंधन''

आज का समय तेज गति और व्यस्तताओं का समय है। संयुक्त परिवारों की जगह छोटे परिवारों ने ले ली है। रोजगार और शिक्षा के कारण भाई–बहन अलग–अलग शहरों और देशों में रहने लगे हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का नया माध्यम तो दिया है, लेकिन कई बार वास्तविक आत्मीय संवाद कम होता जा रहा है। ऐसे समय में रक्षाबंधन हमें अपने रिश्तों की ओर लौटने का अवसर देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में धन, पद और सफलता के साथ रिश्तों की गर्माहट भी आवश्यक है। राखी की एक छोटी–सी डोर वर्षों पुरानी यादों को जीवंत कर सकती है और व्यस्त जीवन में अपनत्व का एक सुंदर क्षण दे सकती है। इसलिए रक्षाबंधन को केवल रस्म के रूप में नहीं, बल्कि रिश्तों को पुनर्जीवित करने के अवसर के रूप में मनाना चाहिए। भाई–बहन एक–दूसरे से संवाद करें, पुराने मनमुटाव दूर करें और परिवार को जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाएं।

''रक्षा का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं''

'रक्षा' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। किसी को शारीरिक संकट से बचाना ही रक्षा नहीं है। किसी के सम्मान की रक्षा करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना, उसके आत्मविश्वास को मजबूत करना और कठिन समय में उसका साथ देना भी रक्षा है। आज भाई द्वारा बहन की रक्षा का संकल्प तभी सार्थक होगा, जब वह उसकी स्वतंत्रता, शिक्षा, निर्णय लेने के अधिकार और स्वाभिमान का भी सम्मान करे। बहन की सुरक्षा का अर्थ उसके सपनों पर पहरा लगाना नहीं, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुरक्षित और समान अवसर देना है। इसी प्रकार बहन भी भाई के सुख–दुख में साथ खड़ी होकर उसके जीवन में विश्वास और आत्मीयता की शक्ति बन सकती है। वास्तविक रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक–दूसरे के सम्मान और अधिकारों का ध्यान रखें।

''परिवार से समाज तक फैलता स्नेह''

रक्षाबंधन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी भावना परिवार से निकलकर पूरे समाज तक पहुंच सकती है। यदि हम अपने परिवार में प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाएंगे तो वही संस्कार समाज में भी दिखाई देंगे। आज आवश्यकता है कि हम रक्षाबंधन को सामाजिक समरसता के पर्व के रूप में भी देखें। जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति की सीमाओं से ऊपर उठकर एक–दूसरे के प्रति मानवीय संवेदना विकसित करें। समाज में कमजोर, असहाय और वंचित लोगों के प्रति सहयोग की भावना भी रक्षा के व्यापक अर्थ को सार्थक करती है। रक्षा का यह भाव प्रेंति तक भी पहुंचना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने प्रियजनों की सुरक्षा चाहते हैं, उसी प्रकार हमें पर्यावरण, पेड़–पौधों, जलस्रोतों और जीव–जंतुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। प्रें ति सुरक्षित होगी तभी मानव जीवन सुरक्षित रह सकेगा।

''आधुनिक युग में राखी का नया संदेश''

आज रक्षाबंधन को नए सामाजिक संदर्भों से जोड़ने की आवश्यकता है। बेटियों की शिक्षा, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, बालिकाओं के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव जैसे विषय भी इस पर्व की भावना का हिस्सा बन सकते हैं। एक भाई अपनी बहन से यह संकल्प ले सकता है कि वह उसकी शिक्षा और सपनों का सम्मान करेगा। एक बहन अपने भाई से यह वचन ले सकती है कि वह समाज की हर बेटी का सम्मान करेगा। परिवार मिलकर यह संकल्प ले सकता है कि घर में बेटा और बेटी के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि राखी का धागा इन संकल्पों से जुड़ जाए तो यह केवल कलाई की शोभा नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन जाएगा।

''रक्षाबंधन हमें क्या सिखाता है?''

रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। विश्वास केवल मांगने से नहीं, निभाने से मिलता है। रिश्ते केवल अधिकारों से नहीं, जिम्मेदारियों से मजबूत होते हैं। यह पर्व हमें अपने माता–पिता, भाई–बहन, मित्रों और समाज के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराता है। यह हमें बताता है कि किसी के जीवन में भरोसे का व्यक्ति बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र हमें यह भी संदेश देता है कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सम्मान, अधिकार और सुरक्षा को अपना दायित्व समझने लगेगा, तब एक अधिक संवेदनशील और सुरक्षित समाज का निर्माण संभव होगा।

''धागा छोटा, संदेश बड़ा''

रक्षाबंधन का धागा छोटा है, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा है। इसमें भाई–बहन का प्रेम है, परिवार का अपनत्व है, समाज की संवेदना है और जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प भी है। आइए, इस रक्षाबंधन पर हम केवल राखी बांधने और मिठाई खिलाने तक सीमित न रहें। हम यह संकल्प लें कि अपने परिवार को जोड़कर रखेंगे, बहन–बेटियों का सम्मान करेंगे, उनके अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, जरूरतमंद के साथ खड़े होंगे और समाज में प्रेम, विश्वास तथा भाईचारे को मजबूत करेंगे। राखी की यह पवित्र डोर हमें याद दिलाती रहे कि ''रिश्तों की असली मजबूती हाथ की कलाई पर बंधे धागे में नहीं, बल्कि दिल में निभाए गए विश्वास और जीवन में उतारे गए कर्तव्य में होती है।'' यही रक्षाबंधन का सच्चा संदेश है। यही भारतीय संस्कृति की आत्मा है। और यही उस रक्षा सूत्र की सार्थकता है, जो एक छोटे से धागे में प्रेम और जिम्मेदारी का पूरा संसार समेटे हुए है।

मैगलगंज में भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं के खिलाफ 31 अगस्त को 'जल सत्याग्रह' करेगा भाकियू सम्राट

मैगलगंज खीरी। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और क्षेत्र की गंभीर जनसमस्याओं से नाराज भारतीय किसान यूनियन (सम्राट) ने शासन–प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह यादव ने उप जिलाधिकारी मितौली को अल्टीमेटम देते हुए ऐलान किया है कि आगामी ३१ अगस्त (सोमवार) को मढ़िया घाट पर हजारों किसानों के साथ विशाल श जल सत्याग्रहश आंदोलन किया जाएगा। भाकियू सम्राट के राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा मोर्चा) जितेन्द्र सिंह यादव ने आरोप लगाया कि पसगवां ब्लॉक की तीन प्रमुख ग्राम पंचायतोंमैगलगंज, खखरा और बेहड़ा जोरावर में विकास कार्यों के नाम पर भारी वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि इन तीनों पंचायतों में एक भी सफाई कर्मी तैनात नहीं है। इसके चलते नालियां पूरी तरह चोक होकर ओवरफ्लो हो रही हैं और नालों पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है, जिससे ग्रामीणों का जीना मुहाल है। ज्ञापन में भ्रष्टाचार का एक और बड़ा उदाहरण देते हुए बताया गया कि नवनिर्मित श्मढ़िया घाट पुलश निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण उद्घाटन के महज ३ महीने के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे राहगीरों और किसानों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है और सरकारी धन की खुली बंदरबांट उजागर हुई है।प्रशासन की होगी पूरी जिम्मेदारीकिसान यूनियन ने चेताया है कि यदि इन समस्याओं का तत्काल निस्तारण नहीं किया गया, तो सोमवार को मढ़िया घाट की नदी में उतरकर उग्र जल सत्याग्रह किया जाएगा। संगठन ने स्पष्ट किया है कि इस आंदोलन के दौरान यदि कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय शासन और प्रशासन की होगी।

यूपी में स्टार्टअप को नई रफ्तार, योगी ने लॉन्च किया मिशन पोर्टलय १०७ स्टार्टअप को ३.४२ करोड़ की प्रोत्साहन राशि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' के पोर्टल का शुभारंभ किया और 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति–२०२६' की पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान १०७ स्टार्टअप को ३.४२ करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि और नौ इनक्यूबेटरों को १.७६ करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकाइयों की संख्या वर्ष २०१७ से पहले के करीब १२० से बढ़कर अब २४ हजार से अधिक हो गई है। इनमें आठ स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहा स्टार्टअप इकोसिस्टम अब उत्तर प्रदेश के प्रति देश और दुनिया की धारणा बदलने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप नीति के तहत १०७ स्टार्टअप को ३.४२ करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। वहीं, नौ इनक्यूबेटरों को १.७६ करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। नए इनक्यूबेटरों को मान्यता प्रमाण–पत्र और विभिन्न स्टार्टअप को प्रोत्साहन प्रमाण–पत्र भी प्रदान किए गए। इनक्यूबेटर ऐसे केंद्र होते हैं, जहां स्टार्टअप को कारोबार बढ़ाने के लिए

मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष २०१४ से पहले भारत में करीब ५०० स्टार्टअप थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर २.५ लाख से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर अनुकूल नीतियों, निवेश और इनक्यूबेशन सुविधाओं ने युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक खास उपलब्धि यह है कि लगभग आधे स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी– बीएचयू और ट्रिपल आईटी जैसे संस्थानों के प्रस्तावों का समर्थन किया है। नए स्टार्टअप के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए गए हैं। वहीं, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए अलग फंड की व्यवस्था की गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में युवा और प्रतिभाशाली श्रम शक्ति की कमी नहीं है। सरकार की भूमिका युवाओं को उनके विचारों और प्रतिभा को कारोबार में बदलने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप और इनक्यूबेशन एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके लिए विश्वास, सरकारी प्रतिबद्धता तथा बेहतर नीतियों पर आधारित मजबूत इकोसिस्टम जरूरी है।

बाघ के हमले में घायल ग्रामीण का हाल जानने पहुंचे डीएफओ, ग्रामीणों को किया जागरूक

लखीमपुर खीरी। बरवर चौकी क्षेत्र की ग्राम पंचायत ककराही के पंचायत भवन में वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ एक आवश्यक बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) तापस मिहिर पहुंचे।हाल ही में ग्राम ककराही के निवासी केपी कुमार (पुत्र शिवकरन लाल) बाघ के हमले में घायल हो गए थे। उनका इलाज शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। डीएफओ तापस मिहिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विशेष रूप से केपी कुमार का हाल–चाल जानने उनके घर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।बैठक के दौरान डीएफओ ने ग्रामीणों को वन्यजीवों से सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि इस समय क्षेत्र में गन्ने की फसल ज्यादा होने के कारण जंगली जानवर वन क्षेत्र से भटककर आबादी और खेतों की तरफ आ जाते हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति खेतों पर अकेले न जाए।हमेशा समूह (ग्रुप) बनाकर ही खेतों की तरफ रुख करें। यदि कोई जंगली जानवर दिखाई दे, तो शोर–शराबा न करें।जानवर दिखने पर तुरंत अपने क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारी को इसकी सूचना दें।बैठक में यह रहे मौजूद,इस मौके पर महेशपुर रेंज का समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। वन विभाग की ओर से मुख्य रूप से डिप्टी रेंजर मोहम्मद उमर, डिप्टी रेंजर सुरेंद्र पाल गौतम, वन दरोगा अखिलेश सिंह, वन दरोगा विजय सिंह और रोहित कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

गोरखपुर से मुंबई का सफर होगा आसान, २८ अगस्त से नियमित चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

लखनऊ। गोरखपुर से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे ने गोरखपुर–बान्द्रा टर्मिनस–गोरखपुर अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस के संचालन का रास्ता साफ कर दिया है। अभी विशेष गाड़ी के रूप में चल रही ०५०५३/०५०५४ गोरखपुर– बान्द्रा टर्मिनस सेवा अब १५०८५/१५०८६ अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में नियमित चलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि १५०८५ गोरखपुर–बान्द्रा टर्मिनस अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस २८ अगस्त २०२६ से हर शुक्रवार गोरखपुर से रवाना होगी। वहीं १५०८६ बान्द्रा टर्मिनस–गोरखपुर अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस २६ अगस्त से हर शनिवार मुंबई से गोरखपुर के लिए चलेगी। नई समय–सारणी के मुताबिक ट्रेन गोरखपुर से सुबह ७:५० बजे रवाना होगी। इसके बाद खलीलाबाद, बस्ती और गोंडा होते हुए ट्रेन बादशाह नगर पहुंचेगी। ट्रेन ऐशबाग से २:०५ बजे और कानपुर सेंट्रल से ३:४५ बजे रवाना होगी। इसके बाद टूंडला, आगरा फोर्ट और बयाना होते हुए गंगापुर सिटी पहुंचेगी.। रात में ट्रेन कोटा, भवानी मंडी, शामगढ़ और रतलाम से गुजरेगी। अगले दिन वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी, पालघर और बोरीवली होते हुए बान्द्रा टर्मिनस शाम ५:४५ बजे पहुंचेगी। यानी गोरखपुर से चलकर ट्रेन उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और मुंबई से जोड़ेगी। वापसी में ट्रेन १५०८६ बान्द्रा टर्मिनस–गोरखपुर अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस शनिवार रात ६रू४५ बजे बान्द्रा टर्मिनस से रवाना होगी । बोरीवली, पालघर, वापी और वलसाड के बाद ट्रेन सूरत और वडोदरा पहुंचेगी। इसके बाद रतलाम, शामगढ़, भवानी मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी और बयाना होते हुए आगरा फोर्ट पहुंचेगी। ट्रेन कानपुर सेंट्रल रात १०:४५ बजे पहुंचेगी। इसके बाद ऐशबाग, बादशाह नगर, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए तीसरे दिन सुबह ६:४५ बजे गोरखपुर पहुंचेगी। रेलवे के अनुसार इस ट्रेन में कुल २२ अमृत भारत कोच लगाए जाएंगे। इनमें सामान्य द्वितीय श्रेणी के ११ कोच, शयनयान श्रेणी के आठ कोच, एक पैंट्री कार और दो एलएसएलआरडी कोच शामिल होंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को एक और साप्ताहिक रेल विकल्प मिलेगा । रेलवे की इस घोषणा से गोरखपुर और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को खास फायदा मिलने की उम्मीद है, खासकर उन यात्रियों को जो कानपुर, आगरा, कोटा, रतलाम, गुजरात और मुंबई की ओर नियमित यात्रा करते हैं।

नेपाल बाढ़ में फंसे यूपीवासियों की मदद को योगी सरकार सक्रिय, SDRF के 32 और PAC के 22 जवान भेजे

लखनऊ। नेपाल में बाढ़ और प्रोंतिक आपदा के कारण उत्पन्न संकट के बीच उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री स्वयं राहत–बचाव की तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। नेपाल में राहत–बचाव अभियान के लिए एसडीआरएफ की एक टुकड़ी भेजी गई है। इसमें ३२ जवान शामिल हैं। इसके साथ ही पीएसी की २६वीं बटालियन के २२ जवानों को भी नेपाल भेजा गया है। सरकार ने स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त जवानों और बचाव उपकरणों की व्यवस्था भी तैयार रखी है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत–बचाव कार्य का विस्तार किया जा सके। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर निकालने के लिए चार रबर बोट उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा अतिरिक्त एसडीआरएफ दल के साथ एल्युमिनियम बोट भी नेपाल भेजी जा रही है। सिंधुरिया क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति और सीमावर्ती जिलों में इसके प्रभाव की लगातार निगरानी कर रही है। राहत आयुक्त कार्यालय के नियंत्रण कक्ष से स्थिति की नियमित जानकारी ली जा रही है और आवश्यकता के अनुसार संबंधित जिलों के प्रशासन के साथ समन्वय किया जा रहा है। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों तक तत्काल मदद पहुंचाना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत–बचाव कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने और जरूरत के मुताबिक सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार प्रभावित नागरिकों और उनके परिजनों को आवश्यक सूचना एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी सक्रिय है।

शादी की खुशियां मातम में बदलीं, गोदभराई के बाद 27 वर्षीय युवक की मौत

हरदोई। नवंबर में शादी होने वाली थी और १२ अगस्त को गोदभराई की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन बुधवार को एक दर्दनाक घटना ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। अरवल थाना क्षेत्र में २७ वर्षीय युवक ने गांव के बाहर बाग में अपनी शर्ट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पलिया पुरवा मजरा उमरौली निवासी अरुण पुत्र सियाराम बुधवार शाम गांव के पश्चिम स्थित सर्वेश के बाग में पहुंचा था। कुछ देर बाद उसका शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरुण की शादी कोतवाली देहात क्षेत्र के बडौरी मजरा नीर निवासी चुन्नीलाल की बेटी से तय हुई थी। १२ अगस्त को उसकी गोदभराई की रस्म पूरी हो चुकी थी और नवंबर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। ऐसे में अचानक उसकी मौत से दोनों परिवारों में मातम पसर गया। कन्नौज के मकरंद नगर निवासी अरुण के चाचा राजेंद्र ने बताया कि बड़े भाई सियाराम की मौत के बाद वह अपने भतीजों की परवरिश कर रहे थे। चार भतीजों में बड़े राहुल की पहले ही मौत हो चुकी है। अरुण तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। परिजनों के मुताबिक, अरुण ने अपना मोबाइल ५०० रुपये में गिरवी रख दिया था। इसकी जानकारी होने पर उसकी मां रामकली ने उसे डांट दिया था। घरवालों का कहना है कि इसी बात से वह नाराज और आहत था। हालांकि, आत्महत्या की वास्तविक वजह क्या रही, पुलिस इसकी जांच कर रही है। घटना के बाद अरवल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के साथ ही मामले की जांच–पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाओं से गूंजा कस्बा खीरी

खीरी टाउन खीरी। जश्ने ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर कस्बा खीरी की फिजाएं नात–ओ–सलाम और "लब्बैक या रसूलुल्लाह" की सदाओं से गूंज उठीं। कस्बे की सदियों पुरानी रूहानी विरासत और हुजूर की मोहब्बत का खूबसूरत रंग जगह–जगह देखने को मिला। विशाल जुलूस, आकर्षक सजावट, कदम–ए–रसूल की जियारत, लंगर और विभिन्न कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। देर रात तक चले कार्यक्रम अमनो–अमान के साथ सम्पन्न हुए। कस्बा खीरी स्थित सुन्नी इमामबाड़े पर परचम कुशाई के बाद विशाल जुलूस रवाना हुआ। जुलूस में बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। हाथों में परचम लिए बच्चे और नौजवान जुलूस की रौनक बढ़ाते नजर आए। विभिन्न मार्गों और मोहल्लों से गुजरते हुए जुलूस में नातिया कलाम और नात–ओ–सलाम की सदाएं गूंजती रहीं। सजी–धजी गाड़ियों पर लगे माइक से नातिया कलाम पेश किए गए। "आमिना का लाल आया" और "लब्बैक या रसूलुल्लाह" जैसी सदाओं के बीच अकीदतमंदों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जुलूस में बच्चों की भागीदारी ने यह संदेश भी दिया कि कस्बा खीरी की रूहानी और धार्मिक परंपराएं नई पीढ़ी तक पहुंच रही हैं। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दरगाह शरीफ की मरकजी मस्जिद में हर वर्ष की तरह इस बार भी कदम–ए–रसूल की जियारत कराई गई। जियारत के लिए सुबह से ही अकीदतमंदों का पहुंचना शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में जायरीन ने अदब और एहतराम के साथ जियारत की। कदम–ए–रसूल की जियारत को लेकर कस्बा खीरी में विशेष अकीदत देखने को मिली। दूर–दूर से पहुंचे लोगों ने इस मुबारक मौके पर अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। जश्ने ईद मिलादुन्नबी को लेकर कस्बे के प्रमुख मार्गों, मोहल्लों और धार्मिक स्थलों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। शाहे विलायत हजरत मखदूम पीर रहमतुल्लाह अलैह की मजार रोशनी और सजावट से जगमगाती नजर आई। मोहल्ला सैय्यदवाड़ा पुलिया चौराहा, बुखारी टोला समेत कई स्थानों पर भी शानदार सजावट की गई। सजावट में कस्बा खीरी की रूहानी विरासत और वर्षों पुरानी परंपरा की झलक दिखाई दी। लोगों ने घरों और गलियों को भी रोशनी से सजाया। रात में अंजुमन आकाये रसूल–खादिमाने मखदूम की ओर से मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया। महफिल में कारी अख्तर रजा, सैय्यद वजी मियां सहित दीगर शोरा–ए–कराम ने हुजूर की शान में नातिया कलाम पेश किए। नातिया कलाम और सलाम के दौरान महफिल में मौजूद अकीदतमंदों का जोश देखते ही बन रहा था। "लब्बैक या रसूलुल्लाह" की सदाओं से माहौल गूंज उठा और हजारों हाथ अकीदत में हवा में लहराते नजर आए। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कस्बे के विभिन्न मोहल्लों में लोगों और अंजुमनों की ओर से लंगर, शर्बत और पानी की सबील का इंतजाम किया गया। जुलूस के रास्ते में अकीदतमंदों का स्वागत किया गया। पूरे आयोजन में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कस्बा खीरी में ईद मिलादुन्नबी का आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कस्बे की रूहानी विरासत, सामूहिक परंपराओं और हुजूर की मोहब्बत की झलक दिखाई दी। बुजुर्गों की अकीदत, नौजवानों का उत्साह और बच्चों की भागीदारी ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। विशाल जुलूस और विभिन्न कार्यक्रम देर रात तक जारी रहे। अंत में जश्ने ईद मिलादुन्नबी का आयोजन शांतिपूर्ण माहौल और अमनो–अमान के साथ सम्पन्न हुआ।

रक्षाबंधन से पूर्व सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राओं ने पालिकाध्यक्ष को बांधा रक्षा सूत्र

गोला गोकर्णनाथ खीरी। रक्षाबंधन के पावन पर्व से एक दिन पूर्व नगर पालिका कार्यालय में सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राओं ने पालिका कार्यालय पहुंचकर पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। छात्राओं के स्नेह से अभिभूत पालिकाध्यक्ष ने सभी बहनों को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि राखी का यह धागा भाई–बहन के प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है। छात्राओं का यह स्नेह मेरे लिए सम्मान के साथ–साथ एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। उन्होंने कहा कि बेटियों और बहनों का सम्मान एवं सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षा और संस्कार के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देना ही सशक्त समाज की पहचान है। सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राओं द्वारा बांधे गए रक्षा सूत्र ने रक्षाबंधन के पर्व को और भी भावपूर्ण बना दिया। इस दौरान छात्राओं और पालिकाध्यक्ष के बीच आत्मीय संवाद भी हुआ।

विश्व संस्कृत दिवस पर आर.एम. ज्ञान दायिनी इंटर कॉलेज में लेखन प्रतियोगिता का आयोजनय मेधावी छात्र पुरस्कृत

लखीमपुर–खीरी। राजाजीपुरम राजापुर स्थित आर एम ज्ञान दायिनी इंटर कॉलेज में विश्व संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष लेखन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा, समृद्ध भारतीय संसेंति और राष्ट्रभक्ति के प्रति रुचि एवं सम्मान की भावना को जाग्रत करना था।प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम' तथा माँ सरस्वती की वंदना 'या कुन्देन्दु तुषारहारधवला' का अत्यंत सुंदर, स्पष्ट और शुद्ध लेखन किया। सभी विद्यार्थियों ने इस आयोजन में पूरे उत्साह और लगन के साथ बढ़–चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के समापन के बाद निर्णायक मंडल द्वारा सभी छात्र–छात्राओं की लेखन–पत्रिकाओं का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया गया। सर्वश्रेष्ठ कॉपियों का चयन लेखन की सुंदरता, अक्षरों की सुसज्जता, स्पष्टता, शुद्धता और सुव्यवस्थित प्रस्तुति के आधार पर किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र–छात्राओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्रदान किया गया। विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक राकेश वर्मा (एडवोकेट) एवं प्रधानाचार्य सचिन शुक्ला ने संयुक्त रूप से विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस गौरवमयी अवसर पर विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें देववाणी संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर प्रेरित रहने का संदेश दिया।

जेपीएनआईसी लखनऊ के संचालन और रखरखाव को UP Cabinet की मंजूरी, ३० साल की लीज पर दिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राजधानी लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) परियोजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए फर्म के चयन को मंगलवार को मंजूरी दे दी। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। खन्ना ने संवाददाताओं से कहा, ''जेपीएनआईसी परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए उच्चतम बोलीदाता मेसर्स वृंदावन ब टलर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को चयनित करने और संबंधित कार्यवाही के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को अधिकृत करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष आया था, जिसे मंजूरी दे दी गई।'' मंत्री ने बताया कि प्रस्ताव के तहत परियोजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए संबंधित कंपनियों को ३० वर्ष की लीज पर दिया जाएगा और इस अवधि को आगे २५ वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण ३० वर्ष की अवधि में पांच प्रतिशत ब्याज सहित करीब ८५७ करोड़ ६६ लाख रुपये सरकार को चुकाएगा। खन्ना ने बताया कि जेपीएनआईसी में अ डिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, विश्वस्तरीय खेल परिसर, बहुउद्देश्यीय खेल कोर्ट और बहुमंजिला पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी, जिनका उपयोग आम जनता भी कर सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के तहत एक कैलेंडर वर्ष में ५० दिनों के लिए इन सुविधाओं का सरकारी संस्थाओं को निशुल्क आवंटन किया जाएगा। जेपीएनआईसी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश की पिछली सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ था। सपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल के फैसले की आलोचना करते हुए 'एक्स' पर कहा, ''भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआईसी (जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर) को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है।'' उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा, ''कमीशन भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गाड़ी का तेल–पानी है और निजीकरण उसका जुगाड़।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ के ८८ गांवों में जल संकट दूर करने के दिए निर्देश

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राजधानी के ८८ गांवों में बढ़ते जल संकट का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पानी जीवन की बुनियादी जरूरत है और इस संकट से निपटने के लिए दीर्घकालिक और तत्काल, दोनों स्तरों पर ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अदालत ने अधिकारियों को प्रस्तावित पांच जल शोधन संयंत्र लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा इस उद्देश्य के लिए चिह्नित ३० झीलों को पुनर्जीवित करने के संबंध में जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने 'उत्कर्ष लोक सेवा संस्थान' द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि ८८ गांवों में जल संकट के स्थायी समाधान के लिए पांच जल शोधन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। बख्शी का तालाब क्षेत्र के नगवामऊ गांव में एक संयंत्र के लिए जिलाधिकारी पहले ही जमीन आवंटित कर चुके हैं। हालांकि, राज्य सरकार से प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी अभी मिलनी बाकी है। मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी) द्वारा संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। अदालत को यह भी बताया गया कि बाकी चार जल शोधन संयंत्र के लिए अभी तक जमीन आवंटित नहीं की गई है। इस पर अदालत ने जिलाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सभी धर्मों के ग्रंथों, धार्मिक रीति–रिवाजों और मान्यताओं के प्रति सम्मान जरूरीः मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर जारी विवाद पर शासन–प्रशासन से शांतिपूर्ण और उचित समाधान निकालने की अपील की है। सुश्री मायावती ने बुधवार को 'एक्स' पर कहा कि डॉ. आंबेडकर ने सभी जाति–धर्म के लोगों को समानता और समतामूलक अधिकार देने वाला संविधान देकर देश को एकजुट

और सशक्त बनाने की गारंटी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के ग्रंथों, धार्मिक रीति–रिवाजों और मान्यताओं के प्रति सम्मान होना चाहिए तथा किसी की धार्मिक भावनाओं की अनदेखी या उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की अस्मिता, सम्मान और पर्दे आदि से जुड़े मामलों को भी संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। स्कूलों में वर्दी, पर्दा, चादर और हिजाब जैसे मामलों को तूल देकर अदालत–कचहरी में विवाद का कानूनी मुद्दा बनाने के बजाय स्थानीय स्तर पर स्कूल प्रबंधन और शासन–प्रशासन को आपसी समझ–बूझ से समाधान निकालना चाहिए, ताकि किसी को संकीर्ण राजनीति करने का अवसर न मिले। बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी सर्वसमाज के सम्मान और लोगों के जान–माल तथा मजहब की सुरक्षा की गारंटी वाली आंबेडकरवादी पार्टी है। उन्होंने कहा है कि धर्म, धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक प्रचलन या मान्यताओं से जुड़े संवेदनशील मामलों पर सभी लोगों को टीका–टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जो देश और जनहित में होगा। सुश्री मायावती ने बदायूं में ड . आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर उत्पन्न विवाद और तनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि शासन–प्रशासन को तत्काल इसका शांतिपूर्ण और उचित समाधान निकालना चाहिए।

प्रभास और ऋषभ शेट्टी ने की 'महाकाली' की तारीफ

मुम्बई। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास और ऋषभ शेट्टी ने निर्देशक प्रशांत वर्मा की आगामी पौराणिक फिल्म 'महाकाली' की पहली झलक की सराहना की है। दोनों सितारों ने विशेष रूप से अक्षय खन्ना के दमदार शुक्राचार्य अवतार और श्रिया रेड्डी की प्रभावशाली मौजूदगी की तारीफ की है। प्रभास ने सोशल मीडिया पर फिल्म की झलक साझा करते हुए प्रशांत वर्मा और पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा कि अक्षय खन्ना और श्रिया रेड्डी झलक में बेहद शानदार नजर आ रहे हैं। वहीं, ऋषभ शेट्टी ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि 'महाकाली' में शुक्राचार्य के युद्ध की पुकार बेहद शक्तिशाली और गूंजदार है। उन्होंने प्रशांत वर्मा और फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं। फिल्म की पहली झलक में अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य अवतार प्रमुख आकर्षण के रूप में सामने आया है। असुरों के गुरु के किरदार में उनका उग्र, प्रभावशाली और रहस्यमयी अंदाज दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। उनके ट्रांसफ र्मेशन और किरदार के इर्द–गिर्द बुने गए रहस्य ने धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महायुद्ध को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। 'महाकाली' में भव्य विजुअल्स, विस्तृत वर्ल्ड–बिल्डिंग और विशाल सिनेमाई दुनिया

देखने को मिलेगी। श्रिया रेड्डी की दमदार मौजूदगी भी फिल्म के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाती है। 'हनु–मान' की सफलता के बाद प्रशांत वर्मा अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स (पीवीसीयू) को आगे बढ़ाते हुए इस फिल्म के जरिए भारतीय पौराणिक कथाओं को भव्य स्तर पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आरके दुग्गल द्वारा प्रस्तुत और रिवाज रमेश दुग्गल द्वारा आरकेडी स्टूडियोज के बैनर तले निर्मित 'महाकाली' का निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लूरू कर रही हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना, श्रिया रेड्डी, भूमि शेट्टी और रोहित सराफ प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म ०८ जनवरी २०२७ को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'द रेवोल्यूशनरीज' के ट्रेलर में रोहित सराफ का दमदार अंदाज

मुम्बई। बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द रेवोल्यूशनरीज' का ट्रेलर जारी हो गया है। ट्रेलर में अभिनेता रोहित सराफ क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल की भूमिका

में नजर आ रहे हैं। इस भूमिका के लिए उन्होंने अपने रूप–रंग और शारीरिक बनावट में भी खास बदलाव किया है। ट्रेलर में रोहित का गंभीर अंदाज और दमदार मारधाड़ वाले दृश्य ध्यान खींचते हैं। उनके लड़ाई के श्य किरदार के जोश, गुस्से और संघर्ष को प्रभावी ढंग से सामने लाते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल के किरदार में रोहित का यह बदला हुआ रूप उनके अब तक के काम से काफी अलग दिखाई देता है। 'द रेवोल्यूशनरीज' एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है, जिसकी कहानी उन युवा भारतीय क्रांतिकारियों पर आधारित है, जो ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए हथियार उठाकर संघर्ष करने में विश्वास रखते थे। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी यह फिल्म ११ सितंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित होगी।

रक्षाबंधन पर सिमरन कौर ने साझा किया खास रिश्ता

मुम्बई। अनमोल टीवी के धारावाहिक 'हमारी राधा' में राधा की भूमिका निभा रहीं अभिनेत्री सिमरन कौर ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने खास पारिवारिक रिश्ते के बारे में बताया। सिमरन सिंगल चाइल्ड हैं, लेकिन अपने कजिन्स को वह सगे भाई–बहनों की तरह मानती हैं। हर रक्षाबंधन पर वह अपने कजिन्स के साथ एक–दूसरे को राखी बांधती हैं।सिमरन ने कहा कि भाई–बहन का रिश्ता केवल राखी बांधने की परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्यार, परवाह और एक–दूसरे का साथ देने से यह रिश्ता मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि एक–दूसरे की रक्षा और देखभाल करना भाई और बहन दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा रक्षाबंधन मेरे लिए हमेशा से बहुत खास रहा है, क्योंकि यह भाई–बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है। मैं सिंगल चाइल्ड हूं, लेकिन खुशकिस्मत हूं कि मेरे कई कजिन्स हैं, जिन्हें मैंने हमेशा अपने भाई–बहन की तरह माना है। इसलिए हर साल हम एक–दूसरे को राखी बांधते हैं। सिमरन ने कहा कि बड़े होने के बाद लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और कई बार अपने भाई–बहनों को यह बताना भूल जाते हैं कि वे उनके लिए कितने खास हैं। रक्षाबंधन जैसे त्योहार उन्हें अपने रिश्तों को याद करने, उन्हें मजबूत बनाने और

अपने प्रियजनों के प्रति प्यार जताने का अवसर देते हैं। उल्लेखनीय है कि 'हमारी राधा' की कहानी भी रक्षाबंधन के दौरान दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। शनाया और राधा के तोहफों की अदला–बदली हो जाती है। राधा के हाथ लगे तोहफे के साथ एक पत्र भी सामने आता है, जिससे गिरधर और शनाया के रिश्ते को लेकर नए सवाल खड़े होने की संभावना है। 'हमारी राधा' का प्रसारण हर रात ६:३० बजे अनमोल टीवी पर होता है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566
सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक